



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 24—जून 30, 2017 (आषाढ 3, 1939)

No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 24—JUNE 30, 2017 (ASADHA 3, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
 (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	569
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	545
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	3
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	967
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को	

*अंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

पृष्ठ सं.	
छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	10683
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंट्स और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	151
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	1357
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.....	*

CONTENTS

Page No.		Page No.	
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	569	by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	545	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	3	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	967	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	10683
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	151
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1357
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 2017

विषय: लोगों के लिए भीम एप्प (भारत इंटरफेस फॉर मनी) रेफरल बोनस योजना

सं. 12(84)/2017-डीपीडी—

1. पृष्ठभूमि और उद्देश्य

- 1.1 डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत नागरिकों को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल प्रशासन और डिजिटल सेवा उपलब्ध करा कर भारत को डिजिटल रूप से एक सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने की परिकल्पना की गई है। डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का संवर्धन डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक सहज विस्तार है और इसमें वित्तीय लेनदेनों को औपचारिक बनाकर भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता मौजूद है।
- 1.2 वित्तीय समावेशन भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है डिजिटल भुगतान प्रणालियां ई-कॉर्मसे से औपचारिक वित्तीय सेवाओं और लाभों तक पहुंच का वादा करती हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें लगातार बाहर रखा जाना जारी है। बैंक-आधारित भुगतान प्रणाली में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद भी, बुनियादी भुगतान सेवाओं की उपलब्धता में काफी अंतर बना हुआ है। प्रौद्योगिकी को अपनाने से देश को कैशलेस अर्थव्यवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है।
- 1.3 वित्त मंत्री ने 1 फरवरी, 2017 को अपने बजट भाषण में "यूपीआई, यूएसएसडी, आधार पे, आईएमपीएस और डेबिट कार्ड के माध्यम से वर्ष 2017-18 के लिए 2500 करोड़ डिजिटल लेनदेन का लक्ष्य" घोषित किया था।
- 1.4 डिजिटल भुगतानों के प्रचार-प्रसार और संवर्धन में, किसी नई सुविधा को बढ़ावा देने के लिए रेफरल योजनाएं व्यापक रूप से उपयोग की जाती हैं, जो मोबाइल एप्लिकेशन सहित बाजार में लॉन्च की जाती हैं और प्रभावी साबित हुई हैं। इसलिए, नागरिकों के बीच भीम एप्प को बढ़ावा देने के लिए एक रेफरल बोनस योजना शुरू की जा रही है।
- 1.5 इस योजना का उद्देश्य भीम एप्प प्लेटफॉर्म पर नए उपयोगकर्ताओं को लाने के लिए भीम एप्प के किसी मौजूदा उपयोगकर्ता को प्रोत्साहित करना और नए उपयोगकर्ताओं को अन्य उपयोगकर्ता के साथ भीम एप्प का उपयोग करके लेनदेन करने या भीम एप्प पर नए उपयोगकर्ताओं को करके लेनदेन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना का उद्देश्य दोहरा है, अर्थात :

 - भीम एप्प के लिए डाउनलोड करने/इंस्टॉल करने और पंजीकरण करने वाले उपयोगकर्ताओं की संख्या में वृद्धि ;
 - भीम एप्प द्वारा लेनदेन की संख्या में वृद्धि

2. लोगों के लिए रेफरल बोनस योजना

- 2.1 इस स्कीम का दायरा केवल भीम एप्प उपयोगकर्ताओं के लिए है। अब तक, योजना की अवधि योजना की शुरुआत की तारीख से 6 महीने हैं और सरकार के निर्देशों के आधार पर इसका नवीनीकरण किया जा सकता है।
- 2.2 एनपीसीआई कार्यान्वयन एजेंसी की भूमिका निभाता है क्योंकि भीम एप्प प्लेटफॉर्म एनपीसीआई के स्वामित्व में है और इसके द्वारा ही संचालित किया जाता है। एनपीसीआई पात्रता की पहचान करने और कैशबैंक की गणना करने के लिए अपने लेनदेन डेटा का उपयोग करता है।

2.3 बोनस रेफरर और भीम एप्प के नए उपयोगकर्ता (रेफरी) दोनों को दिया जाएगा और रेफरल को रेफरी द्वारा निष्पादित केवल 3 सफल वित्तीय लेनदेन (किसी वैध यूपीआई उपयोगकर्ता - "मान्य रिसीवर") के बाद ही सफल माना जाएगा ।

2.4 रेफरल बोनस का भुगतान निम्नलिखित प्रतिमान के अनुसार किया जाएगा :

रेफरल बोनस कैशबैंक राशि	प्रति भीम एप्प उपयोगकर्ता के लिए कुल राशि (रुपए में)
- नया भीम एप्प उपयोगकर्ता (रेफरी) (प्रति व्यक्ति)	25
- रेफरर (प्रति व्यक्ति)	10
कुल रेफरल बोनस राशि	35

2.5 योजना डिजाइन में संस्थाओं के लिए विभिन्न परिभाषाएं अनुबंध 1 में दी गई हैं ।

3. रेफरल बोनस के लिए पात्रता मानदंड

3.1 रेफरल संबंध स्थापित करने के लिए मानदंड—

- क. रेफरी को किसी भी विशिष्ट उपयोगकर्ता के साथ पहले वित्तीय सफल लेन-देन करने की आवश्यकता है।
- ख. रेफरी को प्रथम वित्तीय लेनदेन करने के समय रेफरल कोड के रूप में रेफरर का 10 अंकों वाला मोबाइल नंबर (भीम एप्प पर पहले से पंजीकृत और सक्रिय है) प्रदान करने की आवश्यकता है।
- ग. यदि लेनदेन करने के समय रेफरल कोड दर्ज करने में रेफरी विफल हो जाता है, तो रेफरल संबंध स्थापित नहीं किया जाएगा और इसे बोनस राशि प्राप्त करने के भाग के रूप में नहीं माना जाएगा ।

3.2 रेफरल बोनस राशि कमाने के लिए अर्हता—

- क. रेफरी (जिसने सफलतापूर्वक एक रेफरल कोड दर्ज किया है) को भीम एप्प का उपयोग करके योजना अवधि के दौरान 3 विशिष्ट उपयोगकर्ताओं (किसी भी वैध यूपीआई उपयोगकर्ता - "मान्य रिसीवर") के साथ न्यूनतम 3 सफल वित्तीय लेनदेन को पूरा करना होगा ।
- ख. रेफरी और रेफरर को भीम एप्प उपयोगकर्ता होना चाहिए ।
- ग. कुल लेनदेन मूल्य 50 रुपए के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए ।
- घ. रेफरर किसी ऐसे विशिष्ट उपयोगकर्ता का एक हिस्सा हो सकता है, जो धन प्राप्त कर रहा है ।
- ड. न्यूनतम लेन-देन का मूल्य 1 रुपए होना चाहिए ।

3.3 अन्य प्रासंगिक मानदंड :

- क. योजना के लिए केवल भीम एप्प या *99# से किए गए मान्य अनुमोदित लेनदेनों पर ही विचार किया जाएगा ।
- ख. "रेफरर" और "पहली बार के उपयोगकर्ता" को लेनदेन करने के लिए भीम एप्प या *99 # का उपयोग करना चाहिए ।
- ग. किसी भी वैध यूपीआई उपयोगकर्ता/व्यापारी (दुकानदार) के साथ "भेजें" और "अनुरोध" लेनदेन दोनों को वैध लेनदेन के रूप में माना जाएगा ।
- घ. लेन-देन का मूल्य 1 रु. से 10,000 रु. (और को शामिल करते हुए) के बीच होना चाहिए ।
- ड. अधिकतम रेफरल राशि जो एक रेफरर कमा सकता है, वह प्रति माह 25,000 रुपए है ।
- च. "विशिष्ट भीम एप्प उपयोगकर्ता": एक उपयोगकर्ता को विशिष्ट उपयोगकर्ता के रूप में केवल तभी वर्गीकृत किया जाएगा, अगर उसका मोबाइल नंबर, बैंक खाता किसी अन्य भीम एप्प उपयोगकर्ता के लिए विशिष्ट हैं । नीचे दी गई तालिका में सभी मामले दर्शाए गए हैं, लेकिन यह विशिष्ट उपयोगकर्ताओं की पहचान के लिए सीमित नहीं हैं । एनपीसीआई यह तय करेगा कि ग्राहक एक विशिष्ट उपयोगकर्ता है या नहीं ।

मोबाइल सं.	बैंक खाता	श्रेणी
विशिष्ट	विशिष्ट	नया प्रयोक्ता
विशिष्ट	वही	मौजूदा प्रयोक्ता
वही	विशिष्ट	मौजूदा प्रयोक्ता
वही	वही	मौजूदा प्रयोक्ता

कैशबैंक प्राप्त करने की प्रक्रिया और रेफरी और रेफरर के रिश्ते के संबंध स्थापित करने के लिए विस्तृत तंत्र अनुबंध 2 में वर्णित किए अनुसार हैं।

राजीव बंसल
संयुक्त सचिव

अनुबंध-1

लोगों के लिए रेफरल बोनस योजना के लिए शब्दों/निकायों की परिभाषाएं

अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए अनुसार प्रमुख शब्दों/निकायों की परिभाषाएं निम्नानुसार हैं:

- क. "रेफरर": का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति (भीम एप्प का मौजूदा उपयोगकर्ता) से अभिप्रेत है, जो कि भीम एप्प को किसी नए उपयोगकर्ता को संदर्भित करता है - उसे भीम एप्प उपयोगकर्ता होना चाहिए।
- ख. "रेफरी"/"नया प्रयोगकर्ता": का अर्थ भीम एप्प का पहली बार उपयोग करने वाले उपयोगकर्ता से अभिप्रेत है - जिसे भीम एप्प उपयोगकर्ता होना चाहिए।
- ग. "रेफरल कोड": का अर्थ रेफरर के मोबाइल नंबर से अभिप्रेत है।
- घ. "वैध वित्तीय लेन-देनों": का अर्थ भीम एप्प का उपयोग कर किसी बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में 1 रुपए से अधिक या उसके बराबर और 10,000 रुपए से कम या उसके बराबर की धनराशि के हस्तांतरण से अभिप्रेत है।
- ड. "वैध रेफरल मोबाइल नंबर": का अर्थ भारत में जारी किए गए रेफरर के 10 अंकों के मोबाइल नंबर से अभिप्रेत है, जो पहले से ही एक मौजूदा भीम एप्प उपयोगकर्ता है और जिसने कम से कम एक सफल लेनदेन किया है।
- च. "वैध रिसीवर" - का अर्थ भीम एप्प उपयोगकर्ता/व्यापारी (टुकानदार) सहित यूपीआई के किसी वैध उपयोगकर्ता या व्यापारी से अभिप्रेत है।

अनुबंध-2

रेफरी और रेफरर संबंध स्थापित करने और कैशबैंक का लाभ उठाने के लिए तंत्र

योजना निम्नानुसार आगे बढ़ेगी :

- क. भीम एप्प अनुपयोग को किसी नए उपयोगकर्ता (रेफरी) को संदर्भित करने के लिए मौजूदा भीम एप्प उपयोगकर्ता (रेफरर)।
- ख. नया भीम एप्प उपयोगकर्ता (रेफरी) भीम एप्प का अभिगम शुरू करता है या बैंक में पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर से *99# डायल करके और भीम एप्प पर पूर्ण ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया पूरी कर अर्थात बैंक खाते की डाउनलोडिंग, पंजीकरण और प्राप्त कर शुरू करता है।
- ग. नया भीम एप्प उपयोगकर्ता (रेफर) किसी भी विशिष्ट उपयोगकर्ता के साथ अपना पहला पात्र वित्तीय लेन-देन पूरा करता है।
- घ. रेफरर और रेफरी के बीच रेफरल संबंध स्थापित करने के लिए—
 - i. रेफरी को किसी भी विशिष्ट उपयोगकर्ता (भीम एप्प सहित किसी भी वैध यूपीआई उपयोगकर्ता के लिए - "मान्य रिसीवर") के साथ प्रथम वित्तीय लेनदेन करने के समय रेफरल कोड के रूप में रेफरर का 10 अंकों वाला मोबाइल नंबर (रेफरल कोड) दर्ज करने की आवश्यकता है।

- ii. रेफरल कोड क्षेत्र (एक विकल्प के रूप में) लेनदेन पेज पर दिखाई देगा और केवल नए भीम एप्प उपयोगकर्ता (रेफरी) को अपना पहला वित्तीय लेनदेन करते समय दिखाई देगा।
- iii. *99# के मामले में, रेफरी ऑन-बोर्डिंग के समय रेफरल कोड (विकल्प के रूप में) दर्ज करने का विकल्प चुनेगा।
- iv. प्रणाली यह सत्यापित करेगी कि क्या रेफरर का मोबाइल नंबर वैध रूप से भीम एप्प पंजीकृत है।
- ड. किसी भी 3 विशिष्ट उपयोगकर्ताओं (या तो पी2पी या पी2एम) के साथ कुल 50 रुपए के कम से कम 3 विशिष्ट सफल लेनदेन के पूरा होने पर रेफरर और रेफरी को भीम एप्प में अधिसूचना के माध्यम से बोनस राशि के बारे में सूचित किया जाएगा। इस संदर्भ में रेफरर और रेफरी को भीम एप्प उपयोगकर्ता होना चाहिए, तथापि, वह किसी भी वैध यूपीआई उपयोगकर्ता/व्यापारी के साथ वित्तीय लेनदेन कर सकते हैं।
- च. पात्रता मानदंडों को पूरा करने के बाद रेफरर और रेफरी के बैंक खातों में बोनस की राशि जमा की जाएगी।

विषय: दुकानदारों के लिए भीम एप्प, (भारत इंटरफेस फॉर मनी) कैशबैंक योजना

सं. 12(84)/2017-डीपीडी—

1. पृष्ठभूमि और उद्देश्य

- 1.1 डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत नागरिकों को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल प्रशासन और डिजिटल सेवा उपलब्ध करा कर भारत को डिजिटल रूप से एक सशक्त समाज और जान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने की परिकल्पना की गई है। डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का संवर्धन डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक सहज विस्तार है और इसमें वित्तीय लेनदेनों को औपचारिक बनाकर भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता मौजूद है।
- 1.2 वित्तीय समावेशन भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है डिजिटल भुगतान प्रणालियां ई-कॉर्मस से औपचारिक वित्तीय सेवाओं और लाभों तक पहुंच का वादा करती हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें लगातार बाहर रखा जाना जारी है। बैंक-आधारित भुगतान प्रणाली में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद भी, बुनियादी भुगतान सेवाओं की उपलब्धता में काफी अंतर बना हुआ है। प्रौद्योगिकी को अपनाने से देश को कैशलेस अर्थव्यवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है।
- 1.3 वित्त मंत्री ने 1 फरवरी, 2017 को अपने बजट भाषण में "यूपीआई, यूएसएसडी, आधार पे, आईएमपीएस और डेबिट कार्डों के माध्यम से वर्ष 2017-18 के लिए 2500 करोड़ डिजिटल लेनदेन का लक्ष्य" घोषित किया था।
- 1.4. डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में, खास तौर से भारत जैसे देश में दुकानदार एक बहुत खास भूमिका निभाते हैं जहां छोटे किराना स्टोर, स्थानीय कपड़ों की दुकानें, मॉम-एन-पॉप स्टोर और अन्य स्थानों पर कार्य करने वाले लगभग 90% व्यापारी असंगठित हैं। इनके अलावा, दैनिक छोटे व्यापारी जैसे स्थानीय वेन्डर्स ऑटो/टैक्सी चालक इत्यादि, असंगठित व्यापारियों का एक बड़ा हिस्सा हैं। दुकानदारों के बीच भीम एप्प को बढ़ावा देने के लिए कैशबैंक योजना का शुभारंभ किया जा रहा है।
- 1.5 योजना का उद्देश्य दुकानदारों द्वारा भीम एप्प को न केवल एक बार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, बल्कि उन्हें भीम एप्प (या तो क्यूआर कोड अथवा वीपीए या मोबाइल नम्बर या "पे टू आधार") के जरिए लेनदेनों को प्रोत्साहित करना भी है।

अतः योजना का उद्देश्य दोहरा है अर्थात् :

- भीम एप्प पर पंजीकृत दुकानदारों की संख्या में वृद्धि।
- भीम एप्प का इस्तेमाल करते हुए दुकानदारों से भुगतान संबंधी लेनदेनों की संख्या में वृद्धि।

2. दुकानदारों के लिए भीम एप्प कैशबैंक योजना

- 2.1 इस योजना का कार्यक्षेत्र भीम एप्प का इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों के लिए ही सीमित होगा जब तक कि अन्यथा इसमें कोई संशोधन नहीं किया जाता। योजना अवधि इसके शुभारंभ की तारीख से 6 महीनों के लिए निर्धारित की गई है, जिसकी सरकारी निर्देशों के आधार पर पुनः समीक्षा की जा सकती है।

2.2 एनपीसीआई द्वारा भीम एप्प प्लैटफार्म के स्वीकृत होने के समय से ही एनपीसीआई ने कार्यान्वयन एजेंसी की भूमिका निभाई है और एनपीसीआई द्वारा ही इसे संचालित किया गया है। पात्रता की पहचान और कैशबैंक की गणना करने के लिए एनपीसीआई अपने लेनदेन डाटा का उपयोग करता है।

2.3 दुकानदारों के लिए कैशबैंक प्रोत्साहन स्लैब निम्नानुसार हैं :—

क्रेडिट किए गए लेनदेनों की संख्या (प्रतिमाह)	दुकानदारों के लिए कैशबैंक (प्रतिमाह के अंत में)	शर्तें
50-100	100 रुपए	कम से कम 20 विशिष्ट ग्राहकों से, 25 रुपए प्रति का न्यूनतम लेनदेन
> 100	50 पैसे प्रति लेनदेन अधिकतम 200 रुपए तक	

इस प्रकार दुकानदारों के लिए कैशबैंक प्रतिमाह 100 रुपए से 300 रुपए तक निर्धारित किया जाएगा और 1800 रुपए तक का अधिकतम कैशबैंक जो एक दुकानदार 6 महीनों में कमा सकेगा।

2.4 योजना डिजाइन में निकायों के लिए विभिन्न परिभाषाओं को अनुबंध 1 में संलग्न किया गया है।

3. दुकानदारों के लिए पात्रता मानदंड

3.1 कैशबैंक पाने योग्य दुकानदारों के लिए परिभाषित लेनदेन मानदंड

- क. न्यूनतम 50 क्रेडिट वित्तीय लेनदेन जिसमें से कम से कम 20 लेनदेन वैद्य यूपीआई विशिष्ट ग्राहकों से हैं में भीम एप्प उपयोगकर्ताओं के लेनदेन भी शामिल हैं।
- ख. उपर्युक्त सभी लेनदेनों के लिए न्यूनतम लेनदेन राशि 25 रुपए होनी चाहिए।

3.2 अन्य मानदंड

- (i) दुकानदार भीम एप्प उपभोक्ता होना चाहिए, तथापि वह (स्त्री/पुरुष) लेनदेन मानदंड पूरा करने के लिए किसी भी वैध यूपीआई ग्राहक से क्रेडिट प्राप्त कर सकता है।
- (ii) दुकानदार कैशबैंक योजना एक मासिक कार्यक्रम है और योजना से संबंधित सभी क्रियाकलाप केलेंडर महीनों के अनुसार किए जाते हैं।
- (iii) पात्र दुकानदारों के लिए कैशबैंक प्रोत्साहन को उनके सम्बद्ध खातों में केलेंडर के अगले माह के 10वें दिन या उससे पहले क्रेडिट किया जाएगा।
- (iv) दुकानदार, दुकानदार प्रोत्साहन योजना और रेफर और रेफरी के रूप में ग्राहक रेफरल योजना के भाग के रूप में कैशबैंक या बोनस अर्जित कर सकता है (दुकानदार और रेफर के परस्पर व्यापन स्वीकार्य हैं)।

कैशबैंक प्राप्त करने की प्रक्रिया और एक व्यक्ति की दुकानदार के तौर पर पहचान करने के घोषणा तंत्र की प्रक्रिया का अनुबंध-2 में विस्तारपूर्वक विवरण दिया गया है।

राजीव बंसल
संयुक्त सचिव

अनुबंध-1

दुकानदारों के लिए भीम एप्प कैशबैंक योजना के लिए शब्दावली की परिभाषाएं

अधिसूचना में विवरित किए अनुसार प्रमुख शर्तों/निकायों की परिभाषाएं निम्नानुसार हैं :—

- क. “वैध वित्तीय लेनदेन” : लेनदेन धनराशि ≥ 25 रुपए।
- ख. “वैध प्राप्तकर्ता” - भीम एप्प प्रयोक्ता/दुकानदार सहित कोई भी यूपीआई वैध प्रयोक्ता या दुकानदार हो सकता है।

- ग. “दुकानदार”: भीम एप्प उपभोक्ता होना चाहिए। भीम एप्प के लिए कैशबैंक योजना के उद्देश्य से दुकानदारों को निम्नानुसार परिभाषित किया जाएगा।
- कोई भी निकाय जो वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में संलग्न है। दुकानदार के पास एक विकल्प है कि वह अपने आप को भीम एप्प ऐप के अंतर्गत एक दुकानदार के रूप में घोषित करे।
 - प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए अर्हता हेतु लेनदेन मानदण्ड यह है कि दुकानदार द्वारा एक माह में वैध यूपीआई विशिष्ट ग्राहकों से कम से कम 20 विशिष्ट लेनदेनों से न्यूनतम 50 क्रेडिट लेनदेन प्राप्त किए गए हों जिसमें भीम एप्प प्रयोक्ताओं द्वारा किए गए लेनदेन भी शामिल हैं।
 - लेनदेन मानदंड के आधार पर प्रोत्साहनों के लिए गणना की जाएगी।

अनुबंध-2

कैशबैंक प्राप्त करने और दुकानदार द्वारा घोषणा करने की प्रक्रिया

- क. दुकानदार भीम एप्प और *99# को अपने फोन में डाउनलोड और इन्स्टॉल कर सकते हैं और भीम एप्प में “मैं दुकानदार हूं” टैब पर क्लिक करके दुकानदार के रूप में अपनी घोषणा का एक विकल्प पाएंगे।
- ख. “मैं एक दुकानदार हूं” टैब पर प्रयोक्ता द्वारा एक बार क्लिक करने पर उन्हें भीम एप्प में मांगा गया उचित विवरण अर्थात् व्यवसाय का नाम, सम्पर्क नम्बर (ऑटो पॉपुलेटेड) दुकानदार श्रेणी (ड्राप डाउन), दुकानदार का पता, शहर, पिन-कोड, खाते का प्रकार इत्यादि भरना होगा।
- ग. यह योजना ऐसे सभी दुकानदारों के लिए लागू है, जो भीम एप्प या *99 # पर भुगतान प्राप्त करते हैं।
- घ. यह योजना उन सभी दुकानदारों पर लागू है जो भीम एप्प या *99 # पर भुगतान प्राप्त करते हैं।
- ड. दुकानदारों को प्राप्त कैशबैंक भीम एप्प के पुरस्कार सेक्शन में डिस्प्ले होगा। अपने ग्राहकों से भुगतान एकत्र करने के लिए (क्यू आर कोड, वीपीए, मोबाइल नम्बर, या आधार नम्बर) दुकानदार भीम एप्प पर उपलब्ध किसी भी विकल्प का उपयोग कर सकता है। पुश और पुल दोनों प्रकार के भुगतान इन भुगतानों के लिए अर्हक होंगे।
- च. दुकानदारों के लिए यथापरिभाषित कैशबैंक प्रोत्साहन स्लैब का लक्ष्य प्राप्त करने पर एनपीसीआई एनएसीएच प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए कैशबैंक प्रक्रिया प्रारंभ करता है और दुकानदार को भीम एप्प में नोटिफिकेशन के जरिए कैशबैंक के विषय में सूचित किया जाता है।

दिनांक 8 जून 2017

सं. 3(4)/2017-ईजी-॥—

डिजिधन मिशन

- 1.1 डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत नागरिकों को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल प्रशासन और डिजिटल सेवा उपलब्ध करा कर भारत को डिजिटल रूप से एक सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने की परिकल्पना की गई है। डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का संवर्धन डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक सहज विस्तार है और इसमें वित्तीय लेनदेनों को औपचारिक बनाकर भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता मौजूद है।
- 1.2 वित्तीय समावेशन भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है डिजिटल भुगतान प्रणालियां ई-कॉमर्स से औपचारिक वित्तीय सेवाओं और लाभों तक पहुंच का वादा करती हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें लगातार बाहर रखा जाना जारी है। बैंक-आधारित भुगतान प्रणाली में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद भी, बुनियादी भुगतान सेवाओं की उपलब्धता में काफी अंतर बना हुआ है। प्रौद्योगिकी को अपनाने से देश को कैशलेस अर्थव्यवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है।
- 1.3 भारत वर्तमान में एक डिजिटल अर्थव्यवस्था के सृजन के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाने की दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। जनता के बीच मोबाइल फोनों के तेजी से प्रसार के साथ-साथ डिजिटल प्रौद्योगिकियों, सिग्नल के प्रसार और विस्तार के फलस्वरूप अखिल भारतीय स्तर पर एक ऐसे मजबूत, सुरक्षित और समावेशी डिजिटल भुगतान परिस्थितिकी तंत्र की स्थापना के लिए सरकार द्वारा एक केन्द्रित पहल आवश्यक है, जिसका अभिगम समाज के सभी वर्गों द्वारा किया जा सकता है।

- 1.4 वित्त मंत्री ने 1 फरवरी, 2017 को अपने बजट भाषण में "यूपीआई, यूएसएसडी, आधार पे, आईएमपीएस और डेबिट कार्डों के माध्यम से वर्ष 2017-18 के लिए 2500 करोड़ डिजिटल लेनदेन का लक्ष्य" घोषित किया था और इस बात की घोषणा की थी कि इस प्रयोजन से एक समर्पित मिशन की स्थापना की जाएगी।
- 1.5 इस विज्ञन के अनुक्रम में सरकार एतदद्वारा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के अधीन डिजिधन मिशन नामक एक समर्पित मिशन की स्थापना कर रही है।
2. उद्देश्य और कार्य
- डिजिधन मिशन के निम्नलिखित उद्देश्य और कार्य होंगे:
1. उद्देश्य
 - 2.1 यूपीआई, यूएसएसडी, आधार पे, आईएमपीएस और डेबिट कार्डों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2500 करोड़ डिजिटल लेनदेन का लक्ष्य प्राप्त करना।
 - 2.2 एक मजबूत, सुरक्षित समावेशी राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान परिस्थितिकि तंत्र की स्थापना, वृद्धि और स्थायित्व को बढ़ावा देना और उसकी निगरानी करना।
 - 2.3 सरकार की डिजिटल भुगतान से सेवा प्रदायगी, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और रसीद (ईपीआर) और प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डीबीटी) कार्यक्रम के लिए आवश्यक समर्थकारी और अवसंरचना सृजित करना।
 - 2.4. दक्ष, वहनीय और सुरक्षित डिजिटल भुगतान सेवाओं के लिए उपयुक्त मानक तैयार करना और उन्हें सुकर बनाना।
 - 2.5. डिजिटल भुगतान परिस्थितिकि तंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
 - 2.6. नए डिजिटल भुगतान उत्पादों, प्लेटफॉर्मों, सेवाओं और स्थीय प्रदायगी मॉडलों के विकास सहित अनुसंधान और नवोदयभव को बढ़ावा देना।
 2. कार्य
 - 2.7 डिजिटल भुगतान लेने देनों से संबंधित मौजूदा संस्थागत, कानूनी, सुरक्षात्मक, नीतिगत और नियामक ढांचों की समीक्षा करना; आवश्यक होने पर परिवर्तन करना/सुकर बनाना।
 - 2.8 डिजिटल भुगतानों के लिए संबंधित प्रणाली और बैंक एण्ड प्रौद्योगिकी और स्वीकार्य अवसंरचना का विस्तार करना; डिजिटल भुगतान लेन देनों के लिए नए और व्यवहार्य प्रौद्योगिकी विकल्पों की पहचान करना।
 - 2.9 डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकि तंत्र में आरएण्डडी और नवोन्मेष को सुकर बनाना।
 - 2.10 डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकि तंत्र की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उपाय प्रस्तावित करना।
 - 2.11 लेन-देन प्रभारों को औचित्यपूर्ण बनाने सहित डिजिटल भुगतान लेन-देनों के लिए उपयुक्त वाणिज्यिक और व्यापार मॉडल प्रस्तावित करना।
 - 2.12 डिजिटल भुगतानों यंत्रों के प्रयोग; विशेष रूप से भीम और आधारित भुगतान प्रणालियों को चलाने के लिए नागरिकों, व्यापार स्थापना और सरकारी संस्थानों सहित उपभोक्ता समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाना।
 - 2.13 डिजिटल भुगतानों लेन देन को बढ़ाना देने और उनकी अधिक वृद्धि के लिए उपयुक्त उपर्युक्त वित्तीय प्रोत्साहन कार्यक्रम प्रतिपादित और कार्यान्वित करना।
 - 2.14 सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस), बीमा संबंधी प्रावधानों और सुगम अधिगम के लिए उपयुक्त मानकों और ढांचे को विकसित करके डिजिटल भुगतान यंत्रों में उपभोक्ता के आत्मविश्वास को बढ़ाना।
 - 2.15 अपने संबंधित क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान लेन देनों को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के मंत्रालयों और सर्वजनिक एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।
 - 2.16 डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकि तंत्र के विस्तार के लिए बैंक, वित्तीय संस्थानों, फिनेटेक कंपनियों, टेलीकॉम कंपनियों, भुगतान बैंकों (और अनुज्ञा प्राप्त बैंकों) और अन्य पण्धारकों के साथ समन्वय स्थापित करना।

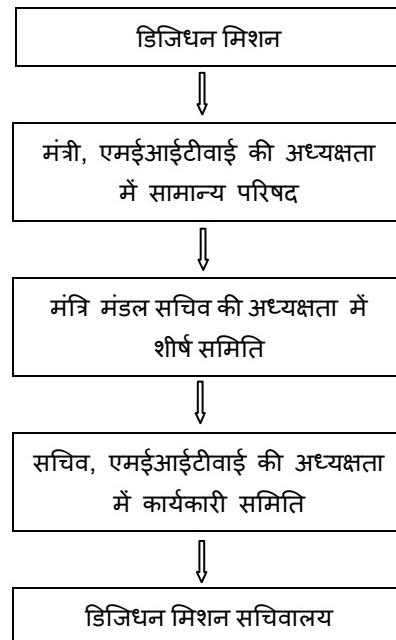
2.17 लोकयुक्त की स्थापना, टोल फ्री हेल्पलाइन और दूसरे उपायों सहित शिकायतों के प्रभावकारी और ठीक समय पर समाधान के लिए उपयुक्त तंत्रों की स्थापना करना ।

2.18 डिजिटल भुगतानों के क्षेत्र में कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न उपायों और डिजिटल भुगतानों के पारिस्थितिक तंत्र पर उनके प्रभाव की निगरानी करना ।

2.19 आवश्यक होने पर कोई अन्य संबंधित या अवशेष नीतिगत उपाय, कार्यक्रम और हस्तक्षेप।

3. मिशन की संरचना

3.1 इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के अंतर्गत डिजिधन मिशन की स्थापना की जा रही है । डिजिधन मिशन की शासन संरचना निम्नानुसार तारीके से होगी :



3.2 शीर्ष समिति और कार्यकारी समिति के गठन से संबंधित विवरण क्रमशः : अनुबंध 'क' और अनुबंध 'ख' में दिए अनुसार हैं ।

3.3 डिजिधन मिशन सचिवालय में एमईआईटीवाई के स्टॉफ और अधिकारियों के साथ-साथ नियामक मामलों, प्रौद्योगिकीय पहलुओं, व्यापार मॉडल, भुगतान अवसंरचना, साइबर सुरक्षा आदि सहत डिजिटल भुगतान से संबंधित मुद्दों पर विषय विशेषज्ञ भी शामिल होंगे । इसमें ऐसा स्टॉफ भी होगा, जो सहक्रिया स्थापित करने और शासन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अन्य संस्थानों के साथ समन्वय हेतु प्रयासों और उनकी भागीदारी के कार्य का पर्यवेक्षण और निगरानी करेगा ।

3.4 राज्य स्तरीय समितियां : डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा देने और उनके प्रसार के लिए राज्यस्तरीय उपायों के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तर पर भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी ।

4. मिशन का बजट

4.1 डिजिधन मिशन अपने कार्यकलापों के लिए आवश्यक होने पर उपर्युक्त स्रोतों, जिनमें डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ी वित्तीय समावेशन निधि, विभागीय योजनाएं, बैंक, अन्य निगमित निकाय शामिल हैं, से संसाधनों जुटाएगा ।

4.2 मिशन के प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यक निधियां विधिवत प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के बजटीय प्रावधानों से उपलब्ध कराई जाएगी ।

5. मिशन के प्रचालन और रणनीति

5.1 डिजिधन मिशन देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के प्राथमिक लक्ष्य और वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2500 करोड़ डिजिटल लेनेदेनी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करेगा ।

5.2 इस उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में यह मिशन प्रचालनात्मक दिशानिर्देश जारी करेगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाएगा। आवश्यक होने पर मिशन द्वारा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् इन्हें जारी किया जाएगा।

राजीव बंसल
संयुक्त सचिव
अनुबंध 'क'

डिजिधन मिशन का गठन: शीर्ष समिति राष्ट्रीय स्तर पर, मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में शीर्ष समिति द्वारा डिजिधन मिशन की निगरानी की जाएगी और जिसमें निम्नलिखित सदस्यों को शामिल किया जाएगा:

मंत्रिमंडल सचिव	अध्यक्ष
सीईओ, नीति आयोग	सदस्य
सचिव, वित्तीय सेवा विभाग	सदस्य
सचिव, व्यय विभाग	सदस्य
सचिव, दूरसंचार विभाग	सदस्य
सचिव, डाक विभाग	सदस्य
सचिव, निवेश और सार्वजनिक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग	सदस्य
उप गवर्नर, आरबीआई	सदस्य
सीईओ, यूआईडीएआई	सदस्य
अध्यक्ष, सीबीआई	सदस्य
प्रबन्ध निदेशक, एनपीसीआई	सदस्य
सचिव, एमईआईटीवाई-मिशन निदेशक	सदस्य सचिव

सचिव, एमईआईटीवाई डिजिधन मिशन के मिशन निदेशक और शीर्ष समिति के सदस्य सचिव होंगे। समिति के पास शीर्ष समिति में अतिरिक्त सदस्यों को सहयोगित करने और शीर्ष समिति के विशेष आंमत्रिकीयों को बैठकों के लिए बुलाने की शक्ति और प्राधिकार है।

अनुबंध 'ख'

डिजिधन मिशन का गठन : कार्यकारी समिति

डिजिधन मिशन में सचिव, एमईआईटीवाई की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति और निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

सचिव, एमईआईटीवाई	अध्यक्ष
सचिव, व्यय विभाग	सदस्य
सचिव, वित्तीय सेवा विभाग	सदस्य
सचिव, दूरसंचार विभाग	सदस्य
सचिव, डाक विभाग	सदस्य
मुख्य सचिव (या उसका/उसकी प्रतिनिधि, जो प्रधान सचिव के स्तर से नीचे नहीं होगा), जो प्रत्येक क्षेत्र से एक राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा। (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उत्तर पूर्वोत्तर) प्रत्येक तिमाही के सदस्यता रोटेशन आधार पर होगी।	सदस्य

सीईओ, यूआईडीएआई	सदस्य
अपर सचिव, एमईआईटीवाई	सदस्य
डीआईपीपी के प्रतिनिधि, (अपर सचिव के स्तर से नीचे नहीं)	सदस्य
आरबीआई प्रतिनिधि (कार्यकारी निदेशक के स्तर से नीचे नहीं)	सदस्य
मुख्य प्रबन्ध निदेशक एनबीएआरडी	सदस्य
महानिदेशक, आई-सर्ट	सदस्य
महानिदेशक, एनआईसी	सदस्य
सलाहाकार, नीति आयोग	सदस्य
सीईओ, इंडिया पोस्ट पेयर्मेंट बैंक	सदस्य
प्रबंध निदेशक, एनपीसीआई	सदस्य
सीईओ, सीससी-एसपीवी	सदस्य
अध्यक्ष, इंडियन बैंक एसोसिएशन	सदस्य
संयुक्त सचिव, एमईआईटीवाई	सदस्य सचिव

समिति के अध्यक्ष के पास आवश्यकता होने पर अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित करने और कार्यकारी समिति के विशेष आमंत्रिकीयों को श्री बैठकों के लिए बुलाने का अधिकार और प्राधिकार होगा।

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

New Delhi, the 5th June 2017

Subject :— BHIM (Bharat Interface for Money) Referral Bonus Scheme for Individuals.

No.12 (84)/2017-DPD—

1. Background and Objective

- 1.1 The Digital India Programme envisions transforming India into a Digitally empowered society and knowledge economy by making available digital infrastructure, digital governance and digital services to every citizen. Promotion of a digital payments ecosystem is a natural extension of the Digital India programme and has the potential to transform India's economy by formalization of financial transactions.
- 1.2 Financial inclusion is one of the foremost challenges for India. Digital payments promises access to formal financial services and benefits from e-commerce, especially for those who continue to be excluded. Despite significant progress in bank-led payment systems, there remains a vast gap in the availability of basic payment services. Adoption of technology can transform the country into a cashless economy.
- 1.3 Finance Minister in his Budget Speech on February 1, 2017 had announced “a target of 2,500 crore digital transaction for 2017-18 through UPI, USSD, Aadhaar Pay, IMPS and debit cards.”
- 1.4 In the promotion of digital payments, referral schemes are widely used to promote adoption of a new facility that is launched in the market, including mobile applications, and have proved effective. Hence, to promote BHIM amongst citizens a Referral Bonus scheme is being launched.
- 1.5 The scheme is intended to incentivize an existing user of BHIM to bring new users on the BHIM platform and encourage the new user to do transaction using BHIM with other users or by referring new users on BHIM. The objectives of the scheme are twofold, viz.:
 - Increase number of users downloading/installing and registering for BHIM;
 - Increase in number of transaction via BHIM

2. Referral Bonus Scheme for Individuals

- 2.1 The scheme scope is only for BHIM users. As of now, the scheme duration is 6 months from the launch date of the scheme, and can be renewed based on government directions.
- 2.2 National Payments Corporation of India (NPCI) takes the role of implementing agency since the BHIM platform is owned and operated by NPCI. NPCI uses its transaction data to identify the eligibility and compute the cashback.
- 2.3 The bonus will be paid to both the referrer and the new user of BHIM (referee) and the referral will be considered successful only after 3 successful financial transactions (to any valid UPI user – “valid receiver”) performed by the referee.
- 2.4 The referral bonus will be paid as per the following pattern:

Referral Bonus Cashback amount	Total Amount (in Rs.) per BHIM user
- New BHIM user (Referee) (per person)	25
- Referrer (per person)	10
Total referral bonus amount	35

- 2.5 The various definitions for the entities in the scheme design are appended in Annexure-1.

3. Eligibility Criteria for referral bonus

3.1 Criteria for establishing Referral relationship –

- a. Referee needs to do first financial successful transaction with the any unique user.
- b. Referee needs to provide the 10 digit mobile number (already registered and active on BHIM) of the referrer as referral code at the time of doing the first financial transaction.
- c. In case, referee fails to enter the referral code at the time of doing the transaction, the referral relationship will not be established and it will not be considered as part of receiving bonus amount.

3.2 Qualification to earn Referral bonus amount –

- a. Referee (who successfully entered a referral code) has to complete minimum 3 successful financial transactions to 3 unique users (to any valid UPI user – “valid receiver”) during the scheme period using BHIM app.
- b. The referee and referrer has to be BHIM User.
- c. The total transactions value should be equal to or more than Rs. 50/-.
- d. Referrer can be a part of the unique user who is receiving the funds.
- e. The minimum transaction value should be Rs.1/-.

3.3 Other relevant criteria:

- a. Only valid approved transactions from BHIM app or *99# will be considered for the scheme.
- b. The “referrer” and the “first time user” should use the BHIM app or *99# to make transactions.
- c. Both “send” and “request” transactions with any valid UPI user / merchant will be considered as valid transactions.
- d. Value of transactions should be between (and including) Rs. 1 to Rs. 10,000.
- e. The maximum referral amount that a referrer can earn is Rs 25,000 per month.
- f. “Unique BHIM users”: A user will be categorized as unique user only if his/her mobile no. bank account are unique to any other BHIM user. Below table showcases all the cases but not limited for identification of unique users. NPCI will determine whether the customer is a unique user.

Mobile No.	Bank Account	Category
Unique	Unique	New User
Unique	Same	Existing User
Same	Unique	Existing User
Same	Same	Existing User

The process for availing cashback and detailed mechanism for establishing a referee and referrer relationship are as detailed in Annexure-2.

RAJIV BANSAL
Joint Secretary

Annexure-1

Definitions of terms/entities for the Referral Bonus scheme for individuals

The definitions of key terms/entities as specified in the notification are as below:

- a. “Referrer”: means a person (existing user of BHIM) who refers BHIM to a new user – Has to be BHIM user.
- b. “Referee”/ “New User”: means a first time user of BHIM – Has to be BHIM user.
- c. “Referral code”: means the mobile number of the referrer.
- d. “Valid financial transactions”: Money transfer from one bank account to another bank account of amount greater than or equal to Rs. 1 and less than or equal to Rs. 10,000 using BHIM.
- e. “Valid Referral Mobile Number” 10 digit mobile number of referrer issued in India who is already an existing BHIM user and have performed at least one successful transaction.
- f. “Valid Receiver” – Can be any UPI valid user or a merchant including BHIM user/merchant.

Annexure-2

Mechanism for establishing a referee and referrer relationship and availing cashback

The Scheme will proceed as follows:

- a. An existing BHIM user (Referrer) to refer BHIM application to new user (Referee).
- b. New BHIM user (Referee) initiates access to BHIM app or by dialing *99# from his/her mobile number registered with bank and complete on-boarding process on BHIM i.e. downloading, registering and fetching the bank account.
- c. New BHIM user (Referee) completes his/her first eligible financial transaction with any unique user.
- d. To establish the referral relationship between referrer and referee –
 - i. Referee needs to enter the referral code (mobile number) of the referrer at the time doing the first financial transaction with any unique user (to any valid UPI user including BHIM – “valid receiver”).
 - ii. The referral code field (as an option) will appear on the transaction page and will be visible only to the new BHIM user (referee) at the time of their first financial transaction process.
 - iii. In case of *99#, the referee will choose the option of entering the referral code (as an option) at the time of on-boarding.
 - iv. System shall validate that if the referrer mobile number is valid BHIM registered.
- e. On completion of minimum 3 unique successful transactions totaling to Rs. 50 to any 3 unique users (either P2P or P2M), the referrer and the referee will be notified about the bonus amount via notification in BHIM app. In this, the referrer and referee has to be BHIM user, however he can perform financial transaction with any valid UPI user / merchant.
- f. The bonus will be credited to the bank accounts of the referrer and the referee after meeting the eligibility criteria.

Subject :—BHIM (Bharat Interface for Money) Cashback Scheme for Merchants

No.12(84)/2017-DPD—

1. Background and Objective

- 1.1 The Digital India Programme envisions transforming India into a Digitally empowered society and knowledge economy by making available digital infrastructure, digital governance and digital services to every citizen. Promotion of a digital payments ecosystem is a natural extension of the Digital India programme and has the potential to transform India’s economy by formalization of financial transactions.
- 1.2 Financial inclusion is one of the foremost challenges for India. Digital payments promises access to formal financial services and benefits from e-commerce, especially for those who continue to be excluded. Despite significant progress in bank-led payment systems, there remained a vast gap in the availability of basic payment services. Adoption of technology can transform the country into a cashless economy.
- 1.3 Finance Minister in his Budget Speech on February 1, 2017 had announced “a target of 2,500 crore digital transaction for 2017-18 through UPI, USSD, Aadhaar Pay, IMPS and debit cards.”
- 1.4 In the digital payments ecosystem, merchants play a very crucial role especially in country like India where nearly 90% of merchants are unorganized like small grocery stores, local apparels outlets, mom-n-pop stores and more. Apart from these, the daily small time merchants like local vendors, auto/taxi drivers etc., constitute of large share of unorganized merchants. To promote BHIM amongst merchants the Merchant Cashback Scheme is being launched.
- 1.5 The scheme aims to incentivize not just one-time adoption of BHIM by merchants, but should also encourage transactions via BHIM mode (either QR code or VPA or Mobile number or “Pay to Aadhaar”).

Hence, the objectives of the scheme are twofold, viz.:

- Increase in number of merchants registered on BHIM
- Increase in number of merchant payment transactions using BHIM

2. BHIM Cashback Scheme for Merchants

- 2.1 The scope of the scheme shall be limited to merchants using BHIM unless revised otherwise. The scheme duration is stipulated as 6 months from the launch date of the scheme, and can be renewed based on government directions.

2.2 National Payments Corporation of India (NPCI) takes the role of implementing agency since the BHIM platform is owned and operated by NPCI. NPCI uses its transaction data to identify the eligibility and compute the cashback.

2.3 The cashback incentive slabs for merchants are:

No. of credit transactions (per month)	Cashback to the merchant (at the end of the month)	Conditions
50-100	Rs 100	From at least 20 unique customers;
> 100	50 paise per transaction maximum upto Rs. 200	Minimum transaction value of Rs. 25 each

Thus the cashback to the merchant will range from Rs. 100 to Rs. 300 per month and the maximum cashback that a merchant can earn will be Rs. 1800 in 6 months.

2.4 The various definitions for the entities in the scheme design are appended in Annexure-1.

3. Eligibility Criteria for Merchant

3.1 Defined Transaction Criteria for Merchants to qualify for cashback are:

- Min of 50 credit financial transactions of which atleast 20 transactions is from valid UPI unique customers including that of BHIM users.
- The minimum transaction value for all above transactions should be Rs. 25/-.

3.2 Other Criteria:

- Merchant should be on BHIM user, however he/she can receive credit from any valid UPI customer to qualify the transaction criteria.
- Merchant cashback scheme is a monthly program and calendar months are considered for the all the activities related to the scheme.
- Cashback incentives to the eligible merchants will be credited to their linked accounts on or before 10th day of the subsequent calendar month.
- Merchant can earn cashback or bonus as part of Merchant Incentive Scheme and Customer Referral Scheme as referrer or referee (the overlap of Merchant and Referrer is acceptable).

The process for availing cashback and declaration mechanism for a person to be identified as a merchant are detailed in Annexure-2.

RAJIV BANSAL
Joint Secretary

Annexure-1

Definitions of terms for the BHIM Cashback scheme for Merchants

The definitions of key terms as specified in the notification are as below:

- “Valid financial transactions”: Transaction amount \geq Rs. 25
- “Valid receiver” – Can be any UPI valid user or a merchant including BHIM user/merchant
- “Merchant”: Has to be BHIM user. For the purposes of the Cashback Scheme for BHIM as merchant would be defined as:
 - Any entity which is engaged in trading of goods and services. The merchant has an option to declare himself into the BHIM app as a merchant.
 - The transaction criteria to qualify to receive incentive is the merchant should have received min of 50 credit transactions from atleast 20 unique transactions from valid UPI unique customers including that of BHIM users in a month
 - The computation for the incentives shall be done on the basis of the transaction criteria.

Annexure 2

Process for merchant declaration and availing cashback

- a. Merchant can download and install the BHIM App or *99# in his phone and will have an option to self-declare himself/herself as merchant by clicking on “I am a Merchant” tab in BHIM app.
- b. Once the user clicks on the “I AM A MERCHANT” tab, he/she has to fill in appropriate details asked by the BHIM App - business name, contact number (auto populated), merchant category (drop-down), merchant address, city, pin-code, account type, etc.
- c. The scheme applies to all merchants who receive payments on BHIM App or *99#.
- d. Reward section in BHIM app would display the cashback received to the merchant.
- e. Merchant can use any mode available on BHIM [QR Code, VPA, Mobile number, or Aadhaar number] to collect the payments from their customers. Both push and pull based payments shall qualify for these payments.
- f. On achieving the cashback incentive slab as defined for the merchants, NPCI initiates the cashback process using NACH platform and the merchant is notified of the cashback via notification in BHIM app.

The 8th June 2017

No. 3(4)/2017-EG-II—

DIGIDHAN Mission

- 1.1 The Digital India Programme envisions transforming India into a digitally empowered society and knowledge economy by making available digital infrastructure, digital governance and digital services to every citizen. Promotion of a digital payments ecosystem is a natural extension of the Digital India programme and has the potential to transform India’s economy by formalization of financial transactions.
 - 1.2 Financial inclusion is one of the foremost challenges for India and Digital payments promises access to formal financial services and benefits from e-commerce, especially for those who continue to be excluded. Despite significant progress in bank-led payment systems, there remains a vast gap in the availability of basic payment services. Adoption of technology can transform the country into a cashless economy.
 - 1.3 India is currently on the cusp of a radical paradigm transition towards the adoption of technology towards the creation of a digital economy. The rapid proliferation of mobile phones across the population, as well as the rise and spread of digital technologies, signals the need for a focused initiative by the Government for establishing a robust, secure and inclusive pan-India digital payments ecosystem, which can be accessed by all sections of the population.
 - 1.4 Hon’ble Finance Minister in his Budget Speech on February 1, 2017 had announced “a target of 2,500 crore digital transaction for 2017-18 through UPI, USSD, Aadhaar Pay, IMPS and debit cards.”; and had announced that a dedicated Mission shall be set up for this purpose.
 - 1.5 In pursuance of this vision, the Government is hereby setting up a dedicated Mission called the DIGIDHAN Mission under the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).
2. Objectives and Functions
- The DIGIDHAN Mission would have the following objectives and functions:
- I. Objectives
 - 2.1 Achieving the target of 2500 crore Digital Payment Transactions in financial year 2017-18 through digital payment modes including UPI, USSD, IMPS, Aadhaar Pay and Debit Cards.
 - 2.2 Promoting and overseeing the establishment, growth and sustenance of a robust, secure and inclusive National Digital Payments ecosystem.
 - 2.3 Creating requisite enabling infrastructure for Government’s Digital Payments Service Delivery, Electronic Payments and Receipts (EPR) and Direct Benefits Transfer (DBT) programme.
 - 2.4 Evolving and facilitating appropriate standards for efficient, affordable and secure Digital Payments Services.
 - 2.5 Ensuring security of digital payments ecosystem.
 - 2.6 Promoting research and innovation, including the development of new digital payment products, platforms, services and sustainable delivery models.

II. Functions

- 2.7 Reviewing the existing institutional, legal, security, policy and regulatory frameworks related to digital payments transactions; and effecting/facilitating changes as required.
- 2.8 Expanding acceptance infrastructure and back-end technology and related systems for digital payments; identification of new and viable technology platforms and options for digital payments.
- 2.9 Facilitating R&D and innovation in the digital payments ecosystem.
- 2.10 Proposing measures to enhance security of digital payments ecosystem.
- 2.11 Proposing appropriate commercial and business models for digital payments including rationalizing transaction charges.
- 2.12 Promoting awareness within user communities including citizens, business establishments and Government organisations to drive usage of digital payments instruments; especially BHIM and Aadhaar based payment systems.
- 2.13 Formulating and implementing appropriate financial incentive programmes and schemes for promotion and greater uptake of digital payments transactions.
- 2.14 Enhancing consumer confidence in digital payments instruments by evolving appropriate standards and frameworks for Quality of Service (QoS), insurance provisions and ease of access.
- 2.15 Coordinating with Ministries of the Union Government, State Governments, and public agencies to promote digital transactions in their respective domains.
- 2.16 Coordinating with Banks, Financial institutions, Fintech companies, Telecom companies, Payments Banks (and other licensed banks) and other stakeholders for expansion of digital payments ecosystem.
- 2.17 Establishing appropriate mechanisms for effective and timely redressal of grievances including establishment of ombudsman, toll-free helplines and other measures.
- 2.18 Monitoring various measures being implemented in the area of digital payments and their impact on the Digital Payments ecosystem.
- 2.19 Any other related or residual policy measures, programmes and interventions that may be required

3. Mission Structure

- 3.1 DIGIDHAN Mission is being setup under the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY). The governance structure of DIGIDHAN Mission will be as follows:



- 3.2 The details regarding the constitution of the Apex Committee and the Executive Committee are as provided in Annexure A and Annexure B respectively

3.3 The DIGIDHAN Mission Secretariat will comprise of MeitY staff and officers as well as subject matter experts on issues concerning digital payments including regulatory matters, technology aspects, business models, payments infrastructure, cyber security etc. It will also have staff to oversee monitoring and coordination efforts and work in partnership with other institutions to drive synergies and ensure convergence.

3.4 State level Committees: At the State level also, there shall be a Committee set-up under the chairmanship of Chief Secretary for implementing State level measures for promotion and proliferation of Digital Payments.

4. Mission Budget

4.1 The DIGIDHAN Mission will mobilize resources, as necessary for its activities, from appropriate sources including the Financial Inclusion Fund (FIF), Departments schemes, Banks and other corporate entities involved in the digital transactions ecosystem.

4.2 Funds required for administrative purposes for the Mission shall be provided through the budgetary provisions of the Ministry of Electronic and Information Technology (MeitY) following due process.

5. Mission Operations and Strategy

5.1 The DIGIDHAN Mission will work towards the primary target of promotion of digital payments in the country and achieving the target of 2500 crore digital transactions in Financial Year 2017/18.

5.2 Towards this aim, the Mission would issue operative guidelines and outline the strategy for achieving its objectives. These would be issued, after approval of the Competent Authority, by the Mission as required.

RAJIV BANSAL
Joint Secretary

Annexure A

Constitution of the DIGIDHAN Mission : Apex Committee

At the national level, the DIGIDHAN Mission shall be monitored by an Apex Committee headed by the Cabinet Secretary and comprising of the following members :

Cabinet Secretary	Chairperson
CEO, Niti Aayog	Member
Secretary, Department of Financial Services	Member
Secretary, Department of Expenditure	Member
Secretary, Department of Telecom	Member
Secretary, Department of Post	Member
Secretary, Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM)	Member
Deputy Governor, RBI	Member
CEO, UIDAI	Member
Chairperson, SBI	Member
MD, NPCI	Member
Secretary, MeitY – Mission Director	Member Secretary

Secretary, MeitY will be the Mission Director of DIGIDHAN Mission and Member Secretary of the Apex Committee. The Committee shall have the authority and power to co-opt additional members in the Apex Committee and call upon Special Invitees to the meetings of the Apex Committee

Annexure B

Constitution of the DIGIDHAN Mission: Executive Committee

DIGIDHAN Mission shall comprise of an Executive Committee headed by Secretary, MeitY and comprising the following members

Secretary, MeitY	Chairperson
Secretary, Department of Expenditure	Member
Secretary, Department of Financial Services	Member
Secretary, Department of Telecom	Member

Secretary, Department of Post	Member
Chief Secretary (or his/her representative not below the level of Principal Secretary) representing one State from each region (North, South, East, West and North East).	Member
Membership shall be on rotation basis each quarter	
CEO, UIDAI	Member
Additional Secretary, MeitY	Member
Representative of DIPP not below the rank of Additional Secretary	Member
RBI representative (not below the rank of Executive Director)	Member
CMD, NABARD	Member
DG ICERT	Member
DG NIC	Member
Advisor, Niti Aayog	Member
CEO, India Post Payments Bank	Member
MD, NPCI	Member
CEO, CSC – SPV	Member
Chairperson, Indian Banks' Association	Member
Joint Secretary, MeitY	Member Secretary

The Chairperson of the committee shall have the authority and power to co-opt additional members as required and also call upon Special Invitees to the meetings of the Executive Committee.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in